

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर 17/2002.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 जनवरी 2004—माघ 10, शक 1925

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 जनवरी 2004

क्रमांक एफ 1-1/2004/1/5.—छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित जिलों की नगर निगम/नगरपालिकाओं/नगर पंचायतों में नीचे दशाये गये स्थानों में उप चुनाव सम्पन्न कराये जा रहे हैं. इन उप चुनावों में मतदान दिनांक 15 जनवरी, 2004 को होना निर्धारित है :—

क्र.	जिले का नाम	नगर निगम/नगरपालिका एवं नगर पंचायत का नाम	वार्ड क्रमांक (रिक्त)	वार्डों की कुल संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	दुर्ग	नगर निगम, भिलाई	6, 19	2 पार्षद

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	महासमुन्द	नगरपालिका परिषद्, महासमुन्द	07	1 पार्षद
3.	धमतरी	नगरपालिका परिषद्, धमतरी	22	1 पार्षद
4.	दुर्ग	नगरपालिका परिषद्, बालौद	07	1 पार्षद
		नगरपालिका परिषद्, बेमेतरा	12	1 पार्षद
5.	राजनांदगांव	नगरपालिका परिषद्, डोंगरगढ़	12	1 पार्षद
6.	रायपुर	नगर पंचायत, आरंग	8	1 पार्षद
7.	महासमुन्द	नगर पंचायत, सरायपाली	13, 14	2 पार्षद
8.	दुर्ग	नगर पंचायत, धमधा	11	1 पार्षद
		नगर पंचायत, अहिवारा	4	1 पार्षद
		नगर पंचायत, पाटन	15	1 पार्षद
9.	बिलासपुर	नगर पंचायत, बिल्हा	6	1 पार्षद
10.	जांजगीर-चांपा	नगर पंचायत, नया बाराद्वार	1, 3, 6	3 पार्षद
11.	कोरिया	नगर पंचायत, बैकुण्ठपुर	6	1 पार्षद
12.	रायगढ़	नगर पंचायत, खरसिया	2	1 पार्षद
13.	जशपुर	नगर पंचायत, पत्थलगांव	14	1 पार्षद

2. अतः आदेशानुसार निवेदन है कि तालिका में दर्शाये गये वाडों में निवास करने वाले कर्मचारियों को मतदान करने हेतु उनके चाहे अनुसार 2 घंटे कार्यालय से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. सूर्य, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2003

FORM M.P.F.C. 3

(See Rule 80)

CERTIFICATE OF TRANSFER OF CHARGE

No. 2884/2003/वा. उ.—Certified that we have in the after noon of this day received charge of the Office of Principal Secretary, Govt. of Chhattisgarh, Commerce, Industry and Public Enterprises Deptt. in pursuance of order No. E-1-5/2003/one/2, dated 26 December, 2003 and that the officer receiving charge travelled during joining time on.....(mention dated).

(For use in Audit Office only)

Relieved Officer.....

Signature.....

Noted in A/R at page.....

(Name in Block Letters)

Noted in leave A/C at page.....

Designation

Leave salary certificate/service statement issued on.....

Auditor Supdt. A.A.G.
A.A.O.

proceeding on transfer
Relieving Officer
Signature

Noted in leave A/C at page.....

(Name in Block Letters) (SHIVRAJ SINGH)

Leave salary certificate service statement issued on.....

Designation Principal Secretary, Commerce, Industry & Public Enterprises Deptt.

Payslip issued on.....

Station Raipur.

Auditor Supdt. A.A.G.
A.A.O.

Date 27-12-2003

Memo of the balances for which responsibility is accepted by the Officer receiving charge cash Rs.

.....permanent Advance Rs.

* Where transfer of charge precedes the issue of formal orders by the competent authority, suitable indication to that effect may be given.

Relieved Officer.....

रायपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2003

क्रमांक एफ 1-7/2003/(6)/11.—राज्य शासन द्वारा रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थायें, छ. ग. रायपुर एवं कार्यालय सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थायें बिलासपुर हेतु सेट-अप (पद संरचना) निम्नानुसार स्वीकृत किया जाता है :—

क्र. (1)	पदनाम (2)	मान्य पद संख्या (3)	वेतनमान (4)	टीप (5)
1.	रजिस्ट्रार	1	12000-16500	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति से.
2.	उप पंजीयक	1	10000-15200	पदोन्नति से
3.	सहायक पंजीयक	2	8000-13500	पदोन्नति से
4.	निरीक्षक	3	5000-8000	पदोन्नति से
5.	सहायक अधीक्षक	1	4500-7000	
6.	आडिटर	3	4500-7000	
7.	स्टेनोग्राफर	1	4500-7000	
8.	सहायक ग्रेड-2	2	4000-6000	
9.	सहायक ग्रेड-3	3	3050-4590	
10.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	1	3050-4590	
11.	स्टेनोग्राफिस्ट	2	3050-4590	
12.	दफ्तरी	1	2610-3540	
13.	भृत्य	3	2550-3200	
14.	प्रोसेस सर्वर	2	2550-3200	
15.	चौकीदार/फर्गुस	2	कलेक्टर दर	
16.	वाहन चालक	1	2610-3540	

कार्यालय, सहायक पंजीयक, बिलासपुर

क्र. (1)	पदनाम (2)	मान्य पद संख्या (3)	वेतनमान (4)	टीप (5)
1.	सहायक पंजीयक	1	8000-13500	पदोन्नति से
2.	निरीक्षक	1	5000-8000	सीधी भरती/पदोन्नति
3.	आडिटर	1	4500-7000	
4.	सहायक ग्रेड-2	1	4000-6000	
5.	सहायक ग्रेड-3	1	3050-4590	
6.	भृत्य	1	2550-3200	
7.	प्रोसेस सर्वर	1	2550-3200	
8.	चौकीदार/फर्राश	1	कलेक्टर दर	
		कुल 8 पद		

2. उपरोक्त पद संरचना निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है :—

- (1) सेवा भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन कर लिया जावेगा.
- (2) पद संरचना के अंतर्गत उपलब्ध रिक्त पद तब तक नहीं भरे जायेंगे जब तक इस हेतु वित्त विभाग से पृथक् से छूट प्राप्त नहीं कर ली जाय.
- (3) चतुर्थ श्रेणी के कोई पद आकस्मिकता (कलेक्टर दर) के पद सहित सीधी भर्ती से नहीं भरे जायेंगे. ये पद अतिशेष कर्मचारियों से ही भरे जायेंगे.
- (4) दर्शाये गये सभी वेतनमान सही है. इस बात की पुष्टि कर ली गई है.

3. इन पदों पर व्यय मांग संख्या-11 मुख्य शीर्ष 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें (200) अन्य व्यापारिक उपक्रमों का विनियमन (255) अन्य व्यवसायिक उपक्रमों के विनियमन-भारतीय साझेदारी विधान का प्रशासन, के अंतर्गत विकलनीय होगा.
4. कार्यालय रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएँ, छ. ग. के लिए स्वीकृत पदों की संरचना में कार्यालय सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएँ, रायपुर संभाग समाहित हो जायेगा.
5. यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 5/8 R-N1 /B 5-1 F/04 दिनांक 7-1-2004 द्वारा महालेखाकार छत्तीसगढ़, रायपुर को पृष्ठांकित की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 जनवरी 2004

क्रमांक एफ 18-18/2003/6/11.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमि. विपणन प्रभाग के लिए निम्नानुसार पद स्वीकृत किये जाते हैं :—

क्रमांक (1)	पदनाम (2)	वेतनमान (3)	पद संख्या (4)	टीप (5)
1.	मुख्य महाप्रबंधक	रु. 12000-16500	1	
2.	महाप्रबंधक	रु. 10000-15200	4	
3.	प्रबंधक	रु. 8000-13500	8	
4.	सहायक प्रबंधक (तक.)	रु. 5500-9000	2	
5.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	रु. 8000-13500	1	
6.	वरिष्ठ लेखापाल	रु. 5000-8000	1	
7.	वरिष्ठ सहायक	रु. 5000-8000	6	
8.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-3	रु. 4500-7000	1	
9.	कैशियर	रु. 4000-6000	1	
10.	कनिष्ठ सहायक ग्रेड-2	रु. 4000-6000	8	
11.	सहायक ग्रेड-3	रु. 3050-4590	4	
12.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	रु. 3050-4590	7	
13.	वाहन चालक	रु. 3050-4590	2	
14.	भृत्य	रु. 2550-3200	5	
15.	चौकीदार	कलेक्टर दर	2	
16.	स्वीपर	कलेक्टर दर	1	
कुल योग				54 पद

2. उपरोक्त पदों की संरचना शर्तें निम्नानुसार होगी :—

- (1) सेवा भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन कर लिया जायेगा.
- (2) पद संरचना के अंतर्गत रिक्त पद तब तक नहीं भरे जायेंगे जब तक इस हेतु वित्त विभाग से पृथक् से छूट प्राप्त नहीं कर ली जाय.
- (3) चतुर्थ श्रेणी के कोई पद आकस्मिकता (कलेक्टर दर) के पद सहित सीधी भर्ती से नहीं भरे जायेंगे. ये पद अतिशेष कर्मचारियों से ही भरे जायेंगे.
- (4) दर्शाये गये वेतनमान सही है. इस बात की पुष्टि विभाग द्वारा कर ली गई है.

3. उपरोक्त पदों पर होने वाला व्यय मांग संख्या-11-मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-5520-छ. ग. स्टेट इन्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड रायपुर से विकलनीय होगा.

4. यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 19/SR-3/B 5/F/04 दिनांक 15-1-04 द्वारा महालेखाकार रायपुर को पृष्ठांकित की गई है.

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2004

क्रमांक एफ 8-3/2003/11/वा. उ.—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल, कोरबा (पूर्व) के बॉयलर क्रमांक एम. पी./4297 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 1-12-2003 से दिनांक 29-2-2004 तक के लिए 3 माह की छूट देता है :—

- (1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
- (2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर, में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
- (3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
- (4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
- (5) छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम 2002 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं
- (6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रशंस्कित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2004

क्रमांक एफ 8-6/2003/11/वा. उ.—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल, कोरबा (पश्चिम) के बॉयलर क्रमांक एम. पी./3656 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 1-12-2003 से दिनांक 31-12-2003 तक के लिए 1 माह की छूट देता है :-

- (1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जायेगी.
- (2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
- (3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
- (4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
- (5) छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम 2002 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं
- (6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभय कुमार मिश्रा, अवर सचिव.

कृषि (सहकारिता) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2003

FORM M. P. F. C. 3

(See Rule 80)

CERTIFICATE OF TRANSFER OF CHARGE

No. 1514/कृषि/2003-04.—Certified that we have in the fore of this day respectively made over and received charge of the Office of Secretary, Co-operation in pursuance of order No. *E-1-5/2003/one/2, dated 26-12-2003 and that the officer receiving charge travel during joining time on 29-12-2003 (mention date).

(For use in Audit Office only)

Relieved Officer.....

Signature. Sd./-

Noted in A/R at page.....

(Name in Block Letters) P. C. DALEI

Noted in leave A/C at page.....

Designation SECRETARY CO-OPERATION, RAIPUR
29-12-2003

Leave salary certificate/service issued on.....

Auditor Suptd. A.A.G.
A.A.O.

Proceeding on transfer/leave/retirement

Relieving Officer.....

Signature. 'Sd/-

Noted in A/R at page.....

Noted in leave A/C at page.....

(Name in Block Letters) C. K. KHAITAN

Payslip issued on.....

Designation SECRETARY CO-OPERATION

Station Raipur.

Auditor Suptd. A.A.G.
A.A.O.

Date 29-12-2003

Memo of the balances for which responsibility is accepted by the Officer receiving charge cash Rs.

.....permanent Advance Rs.

* Where transfer of charge precedes the issue of formal order be the competent authority, a suitable indication to that effect may be given.

Relieved Officer.....

Forwarded to.....

Relieving Office.....

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. दवे, अवर सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2004

क्रमांक 5984/बी-6/26/04/14-2.—राज्य शासन कृषि विभाग की अधिसूचना क्र./4326/कृषि/2001, दिनांक 17-10-2001, डॉ. खूबचन्द बघेल "कृषक रत्न पुरस्कार" के नियम के अनुक्रमांक-6-जूरी-के सरल क्रमांक-1 में विशेष सचिव, कृषि-अध्यक्ष के आगे शब्द "सचिव अथवा" जोड़ा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एल. जैन, उप-सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2004

क्रमांक 46/47/13/ऊर्जा/04.—राज्य शासन, ऊर्जा विभाग के आदेश क्रमांक 131/स.ऊ./2003, दिनांक 18-4-2003 द्वारा श्री के. एस. अरोरा, कार्यपालिक संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल को विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 5(4) के अंतर्गत अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सदस्य (पारेषण एवं वितरण), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल नियुक्त किया गया था. राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि श्री के. एस. अरोरा को सदस्य (पारेषण एवं वितरण) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल, के प्रभार से तत्काल प्रभाव से मुक्त किया जाए.

2. अन्य आदेश तक सदस्य (पारेषण एवं वितरण), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल का प्रभार श्री ए. के. राय, सदस्य (उत्पादन), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के पास रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. बंजारे, उप-सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2003

FORM M. P. F. C. 3

(See Rule 80)

CERTIFICATE OF TRANSFER OF CHARGE

No. 365/आजाक/2003-04.—Certified that we have in the afternoon of this day respectively made over and received charge of the Office of Principal Secretary, ST & SC Development in pursuance of order No. *E-1-5/2003/one/2, dated 26-12-2003 and that the officer receiving charge travel during joining time on 29-12-2003 .(mention date).

(For use in Audit Office only)

Relieved Officer.....

Signature. Sd/-

Noted in A/R at page.....

(Name in Block Letters) SERJIUS MINJ

Noted in leave A/C at page.....

Designation PRINCIPAL SECRETARY ST & SC DEV.

Leave salary certificate/service statement issued

on.....

Auditor Suptd. A.A.G.
A.A.O.

Proceeding on transfer/leave/retirement

Relieving Officer.....

Signature Sd/-

Noted in A/R at page

Noted in leave A/C at page.....

Payslip issued on.....

(Name in Block Letters) P. C. DALÉI

Designation SECRETARY CO-OPERATION

Station Raipur

Auditor Suptd. A.A.G.
A.A.O.

Date 29-12-2003

Memo of the balances for which responsibility is accepted by the Officer receiving charge cash Rs.
permanent Advance Rs.

* Where transfer of charge precedes the issue of formal order be the competent authority, a suitable indication to that effect may be given.

Relieved Officer.....

Forwarded to.....

Relieving Office.....

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 सी. के. देवानी, अवर सचिव.

जल संसाधन विभाग
 मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2003

FORM M. P. F. C. 3

(See Rule 80)

CERTIFICATE OF TRANSFER OF CHARGE

No. 7076/जसंसा/2003.—Certified that we have in the fore/afternoon of this day respectively made over and received charge of the Office of सचिव, जल संसाधन विभाग in pursuance of order No. *ई-1-5/2003/112 dated 26-12-2003 and that the officer receiving charge travelled during joining time on 29 दिसम्बर, 2003 (अपराह्न) (mention dates).

(For use in Audit Office only)

Relieved Officer.....

Signature. Sd/-

Noted in A/R at page.....

(Name in Block Letters) (के. डी. पी. राव)

Noted in leave A/C at page.....

Leave salary certificate/service statement issued on.....

Designation विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग,
 मंत्रालय.

Auditor Supdt. A.A.G.
A.A.O.

Proceeding on transfer/leave/retirement

Relieving Officer.....

Signature. Sd/-

Noted in A/R at page.....

(Name in Block Letters) सरजियस मिन्ज

Noted in leave A/C at Page.....

Designation उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय.

Payslip issued on.....

Station Raipur.

Auditor Supdt. A.A.G.
A.A.O.

Date 29-12-2003 (अपरान्ह)

Memo of the balances for which responsibility is accepted by the Officer receiving charge cash Rs.

.....permanent Advance Rs.

* Where transfer of charge precedes the issue of formal orders by the competent authority, a suitable indication to that effect may be given.

Relieved Officer.....

Forwarded to.....

Relieving Officer.....

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 जनवरी 2004

क्रमांक 266/21-ब/छ. ग./04.—श्री जे. आर. रोशन, अधिवक्ता, जशपुर नगर, को फास्ट ट्रेक कोर्ट में अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक के पद पर इस विभाग के आदेश क्रमांक 1577/21-ब/4035, दिनांक 6-8-2001 के द्वारा नियुक्त किया गया था. श्री जे. आर. रोशन की सेवाओं की अब आवश्यकता न होने के कारण राज्य शासन, एतद्वारा श्री जे. आर. रोशन, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, जशपुर नगर, की सेवायें समाप्त करते हुए, उन्हें अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक के पद से हटाये जाने संबंधी, एक माह का नोटिस जारी करता है.

तदनुसार आज दिनांक 9-1-2004 से एक माह के पश्चात् अर्थात् दिनांक 8-2-2004 से श्री जे. आर. रोशन की सेवायें स्वमेव समाप्त हो जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभात शास्त्री, उप-सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2004

क्रमांक एफ 3-1/2003/55.—चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर में बड़ी संख्या में पद रिक्त है तथा छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम-1987 के अनुसार आवश्यक अनुभव न होने के कारण पदोन्नति नहीं हो पा रही है। राज्य शासन द्वारा अनुभव में 2 वर्ष की छूट प्रदान की गई, परन्तु इसके बाद भी अनुभव की कमी के कारण अनेक पद रिक्त है। राज्य शासन चाहता है कि पदों की पूर्ति शीघ्रता से हो सके।

2. अतः राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम-1987 की अनुसूची में सह-प्राध्यापक तथा प्राध्यापक के पदों को भरने के लिये नियमों में एक बार का शिथिलीकरण करते हुए, इन पदों को पदोन्नति के स्थान पर सीधी भरती से भरने की स्वीकृति प्रदान करता है। इसे भविष्य के लिये पूर्वोदाहरण नहीं माना जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार धुव, अवर सचिव।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2004

क्रमांक एफ 6-1/खाद्य/2004/29.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए “छत्तीसगढ़ शासन के कार्य नियम” (Chhattisgarh Government rules of business) के नियम (13) के अधीन अनुपूरक अनुदेश भाग (5) के अनुदेश क्रमांक 2 “क” एक के अनुसार मुझमें निहित प्राधिकार के अनुसरण में, मैं (मेघाराम साहू) मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, छत्तीसगढ़ एतद्वारा इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 6-168/95/29-2, दिनांक 11-1-2001 को निरस्त करता हूँ एवं निर्देश देता हूँ कि दिनांक 31-8-97 तक के समस्त अपील/पुनरीक्षण, जो राज्य शासन के समक्ष लंबित है एवं तत्पश्चात् प्रस्तुत अपील/निगरानी प्रकरणों की सुनवाई एवं निराकरण मेरे द्वारा किया जाएगा।

हस्ता./-

(मेघाराम साहू)
मंत्री

राजस्व विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2004

FORM M. P. F. C. 3

(See Rule 80)

CERTIFICATE OF TRANSFER OF CHARGE

No. 01/राजस्व/2004.—Certified that we have in the fore/afternoon of this day respectively made over and received charge of the Office of राजस्व विभाग in pursuance of order No. *ई-1/24/2003/एक/2, dated 1 जनवरी 2004 and that the officer receiving charge travelled during joining time on 1 जनवरी 2004 (पूर्वाह्न) (mention dates).

(For use in Audit Office only)

Relieved Officer.....

Signature.....

Noted in A/R at page
Noted in leave A/C at page.....
Leave salary certificate/service statement issued on.....

(Name in Block Letters)

Designation

Auditor Supdt. A.A.G.
A.A.O.

Proceeding on transfer/leave/retirement

Relieving Officer.....

Signature.....

Noted in A/R at page.....
Noted in leave A/C at page.....

(Name in Block Letters) (अवध बिहारी)

Designation संयुक्त सचिव

Payslip issued on.....

Station रायपुर

Auditor Supdt. A.A.G.
A.A.O.

Date 01 जनवरी 2004

Memo of the balances for which responsibility is accepted by the Officer receiving charge cash Rs.

.....permanent Advance Rs.

* Where transfer of charge precedes the issue of formal orders by the competent authority, a suitable indication to that effect may be given.

Relieved Officer.....

Forwarded to.....

Relieving Officer.....

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. तिवारी, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2004

क्रमांक /क/वा.भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 4 अ-82 वर्ष 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	गोईन्दा प. ह. नं. 148/44	25.04	कार्यपालन यंत्री, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग रायपुर.	ग्राम गोईन्दा प.ह.नं. 148/44 तहसील आरंग की निजी भूमि को राजीव आगमेन्टेशन (व्यप- वर्तन) योजना के अंतर्गत डूबान क्षेत्र हेतु भू-अर्जन.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2004

क्रमांक /क/वा.भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 5 अ-82 वर्ष 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	छटेरा प. ह. नं. 149/47	22.77	कार्यपालन यंत्री, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग रायपुर.	ग्राम छटेरा प.ह.नं. 149/47 तहसील आरंग की निजी भूमि को राजीव आगमेन्टेशन (व्यप- वर्तन) योजना के अंतर्गत डूबान क्षेत्र हेतु भू-अर्जन.

रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2004

क्रमांक /क/वा./अ.वि.अ./02 अ-82, 2003-2004. —चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध लागू है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	बरौदा प. ह. नं. 72/15	8.89	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विमानन विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर.	रायपुर (माना) विमानतल के विस्तार हेतु अनिवार्य भू- अर्जन.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2003

पृष्ठांकन क्र. 06/अ-82/2002-2003. —चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	आमामुड़ा	1.426	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्डारोड.	वेस्ट वियर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2003

पृष्ठांकन क्र. 07/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	आमामुड़ा	1.510	कार्यपालन, अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्डुरोड.	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2003

पृष्ठांकन क्र. 08/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	खैरझिटी	7.392	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्डुरोड.	डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 सितम्बर 2003

पृष्ठांकन क्र. 09/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	खैरझिटी	1.000	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्डुरोड.	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2003

पृष्ठांकन क्र. 10/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	पंडरापथरा	3.203	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्डुरोड.	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2003

पृष्ठांकन क्र. 11/अ-82/2002-2003.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	बानाबेल	0.579	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्डारोड.	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 जनवरी 2004

क्रमांक 4 अ/82/2003-2004.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्डारोड	महोरा	34.698	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मरवाही, मुख्यालय पेण्डारोड.	बगड़ी जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्डारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2003

क्रमांक 18/ अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्डारोड	डाहीबहरा	0.558	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मरवाही, मुख्यालय पेण्डारोड.	डाहीबहरा जलशय के लघु नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्डारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 जनवरी 2004

क्रमांक 3 अ/82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्डारोड	सेंवरा	43.820	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मरवाही, मुख्यालय पेण्डारोड.	बगड़ी जलशय के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्डारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 जनवरी 2004

क्रमांक 5 अ/82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्डारोड	मझगावां	22.592	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मरवाही, मुख्यालय पेण्डारोड.	बगड़ी जलाशय के डूब एवं बण्ड क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्डारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 जनवरी 2004

क्रमांक 2 अ/82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्डारोड	कोरजा	0.911	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मरवाही, मुख्यालय पेण्डारोड.	खुदरी जलाशय के शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्डारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 जनवरी 2004

क्रमांक 6 अ/82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्डारोड	अड़भार	3.154	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मरवाही, मुख्यालय पेण्डारोड.	बगड़ी जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्डारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुंद, दिनांक 9 जनवरी 2004

क्रमांक 4458/अ.वि.अ./भू-अर्जन/01 अ/82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक 1 सन् 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	सरायपाली	पोटापारा प.ह.नं. 01	3.34	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, महासमुंद (छ. ग.).	धीपापानी जलाशय में नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 9 जनवरी 2004

क्रमांक 4458/अ.वि.अ./भू-अर्जन/02 अ/82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	बसना	लोहरिनडीपा प.ह.नं. 02	1.75	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द (छ. ग.).	थीपापानी जलाशय में नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 9 जनवरी 2004

क्रमांक 4458/अ.वि.अ./भू-अर्जन/03 अ/82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	बसना	टीपा प.ह.नं. 02	1.53	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द (छ. ग.).	थीपापानी जलाशय में नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 9 जनवरी 2004

क्रमांक 4458/अ.वि.अ./भू-अर्जन/04 अ/82/2003-04. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	गोधामुड़ा प.ह.नं. 12	2.78	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द (छ. ग.)	लमकेनी सरायपाली जलाशय में दायीं तट नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 9 जनवरी 2004

क्रमांक 4458/अ.वि.अ./भू-अर्जन/05 अ/82/2003-04. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	सरायपाली प.ह.नं. 12	0.08	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द (छ. ग.).	लमकेनी सरायपाली जलाशय में दायीं तट नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 9 जनवरी 2004

क्रमांक 25/अ.वि.अ./भू-अर्जन/06 अ/82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुंद	बैतारी प.ह.नं. 34	0.28	कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण संभाग (सेतु निर्माण) रायपुर	बसना-बम्हनी बिलाईगढ़ मार्ग बतौरी नाला सेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिन्दर कौर द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 8 जनवरी 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 03/अ-82/सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	तुरंगा प.ह.नं. 42	2.379	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन रायगढ़ (छ. ग.)	तुरंगा जलाशय के लिये भू- अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 8 जनवरी 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 04/अ-82/सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	रनभांठा प.ह.नं. 40	0.166	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन रायगढ़ (छ. ग.).	रनभांठा व्यपवर्तन हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 8 जनवरी 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 05/अ-82/सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	सुटुपाली प.ह.नं. 42	1.558	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन रायगढ़ (छ. ग.).	सुटुपाली जलाशय के लिये भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 8 जनवरी 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 06/अ-82/सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	मचिदा प.ह.नं. 42	0.817	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन रायगढ़ (छ. ग.).	सुदुपाली जलाशय योजना के डूब हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 8 जनवरी 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 07/अ-82/सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कलमी प.ह.नं. 42	3.253	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन रायगढ़ (छ. ग.).	सुदुपाली जलाशय के लिए भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 9 दिसम्बर 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 9/अ-82/सन् 2003-2004.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	ढिमानी	0.020	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 9 दिसम्बर 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 10/अ-82/सन् 2003-2004.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	टेमटेमा	1.124	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 2 नवम्बर 2003

क्र. 1/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-जैजैपुर
(ग) नगर/ग्राम-तुषार, प. ह. नं. 13
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.381 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

331	0.028
332	0.057
330/2	0.053
330/5	0.047
324/1	0.057
218	0.008
219/2	0.014
211	0.012
210	0.032
366	0.038
203/4	0.053
369/3	0.012
302/4	0.038
334	0.077
340	0.028
344/3	0.024
344/4	0.053
346	0.004

(1)

(2)

347	0.012
359/1	0.065
369/1	0.018
367	0.004
364/2	0.008
369/6	0.077
369/10	0.099
396/1	0.028
396/4	
378/5	0.024
378/4 क	0.125
378/4 ख	0.073
385/1	0.024
385/2	0.028
378/11	0.081
388/4	0.012
388/5	0.012
388/6	0.012
359/2	0.012
388/7	0.012
388/1	0.004
213	0.016

योग : 1.381

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—कंचदा उप वितरक नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 2 नवम्बर 2003

क्र. 5/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

अनुसूची		खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1) भूमि का वर्णन-		(1)	(2)
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)			
(ख) तहसील-जैजैपुर		378/2	0.016
(ग) नगर/ग्राम-तुषार, प. ह. नं. 13		379	0.040
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.036 हेक्टेयर		380/1	0.053
		387	0.032
		390/6	0.012
		459	0.012
		456/1	0.020
		454/1	0.04
		441/1	0.036
		440	0.016
		912	0.008
		913/2	0.024
		455/3	0.024
		442/5	0.004
		914/2	0.004
		872/3	0.036
		839/1	0.012
		838/1	0.028
		838/4	
		828/2	0.028
		829	0.028
		848/1	0.024
		849	0.024
		850	0.036
		827/21	-
योग			0.541

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-तुषार माइनर नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 13 नवम्बर 2003

क्र. 10/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बोडसरा, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.541 हेक्टेयर

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 13 नवम्बर 2003

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-कचंदा उप वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 11/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 16 नवम्बर 2003

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
 (ख) तहसील-जैजैपुर
 (ग) नगर/ग्राम-गलगलाडीह, प. ह. नं. 13
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.656 हेक्टेयर

क्र. 12/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

297/2	0.040
297/3	0.028
297/1 ख	0.004
297/4	0.028
314/1	0.024
311	0.034
327	0.016
276/1	0.008
206	0.008
215/1	0.008
275	0.016
191	0.040
257/3	0.012
259	0.032
205	0.004
318	0.004
215/2	0.008
210	0.004
564	0.004
569	0.008
631/1	0.012
661/2	0.040
662/1	0.016
660	0.004
666	0.020
667	0.012
653/1	0.016
653/2	0.045
715/1 ब	0.117
715/1 छ	0.016
715/1 ह	0.028

योग 0.656

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-गलगलाडीह माइनर नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
 (ख) तहसील-जैजैपुर
 (ग) नगर/ग्राम-कुटराबोर, प. ह. नं. 19
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.377 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

773/1	0.089
776/4	0.053
776/6	0.101
776/5	0.105
824	0.129
1648	0.008
776/3	0.012
815/2	0.012
828	0.065
822	0.016
821/1	0.016
819/4	0.049
819/5	0.117
815/1	0.097
815/3	0.049
816	0.008
1103/1	0.028
792/6	0.073
812/2	0.032
1153	0.057
792/2	0.020
1152	0.008
913, 914, 915, 916, 917	0.057

(1)	(2)	अनुसूची	
1114/1	0.065	(1) भूमि का वर्णन-	
1108	0.036	(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)	
1107	0.053	(ख) तहसील-जैजैपुर	
1106	0.053	(ग) नगर/ग्राम-बरदुली, प. ह. नं. 19	
1105	0.040	(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.446 हेक्टेयर	
1104/1	0.008	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
1103/2	0.032		
1103/3	0.032	(1)	(2)
1103/4	0.024		
1099/3	0.073		
1099/1	0.073	418/2	0.210
1099/2	0.020	438/5, 438/6, 556/2	0.129
1154	0.057	463	0.036
911/2	0.012	464/1	0.008
801	0.073	462/2	0.129
1643/1	0.004	471, 472	0.012
1643/2	0.036	468/1	0.008
1645	0.036	467	0.049
1650/3	0.231	468/2	0.020
1650/1, 2	0.073	499/3	0.020
1650/4	0.016	514/1	0.020
1191/1	0.040	514/2	0.101
912/1	0.020	513	0.024
909/3	0.069	515/3	0.012
		499/4	0.032
योग	2.377	515/2 ख	0.012
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-बरदुली शाख वितरक नहर निर्माण हेतु (पूरक).		500	0.008
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.		501	0.004
		540/2	0.032
		540/3	0.024
		537	0.012
		535/2	0.020
		538	0.028
जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 16 नवम्बर 2003		660, 661	0.093
		535/5	0.008
		535/3	0.065
		531	0.036
		664/1	0.004
		555/2	0.004
		555/1, 555/3	0.045
		685	0.032
		686	0.032

क्र. 13/सा-1/सात.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

(1)	(2)	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
		(1)	(2)
663/1	0.016		
664/7	0.020		
664/2	0.032	89/1, 91/2	0.061
676	0.008	89/2	0.008
664/4	0.012	79/3	0.004
468/3	0.008	79/2	0.053
439/2	0.049	79/1	0.129
540/1	0.004	78/2	0.022
540/9	0.012	76/2	0.008
540/10	0.016	76/1	0.061
		73/3	0.085
योग	1.446	75/1	0.032
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-बरदुली शाखा वितरक नहर निर्माण हेतु (पूरक).		74/1	0.061
		41/1	0.016
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांचगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.		34/3	0.012
		74/2	0.012
		35	0.065
		36/1	0.077
		37/2	0.016
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. आर. सारथी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.		37/1	0.020
		38/1	0.032
		39/2	0.032
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग		39/3	0.004
		40	0.089
		43/2, 6/1	0.065
		44/2	0.101
खरसिया, दिनांक 16 दिसम्बर 2003		77/1	0.093
		77/2	0.101
भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		26/1	0.097
		26/3	0.150
		25/1	0.069
		21/3	0.275
		304/2	0.065
		325/3	0.020
		304/1	0.049
		306/2	0.045
		311/1	0.061
		312	0.024
(1) भूमि का वर्णन—		335/1	0.032
(क) जिला-रायगढ़		309/2	0.008
(ख) तहसील-रायगढ़		310/2	0.069
(ग) नगर/ग्राम-सरवानी		313/1, 313/2	0.142
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.960 हेक्टेयर			

अनुसूची

(1)	(2)	खसिया नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
		(1)	(2)
319/1 ख	0.016		
319/1 ग	0.081		
320/1	0.049	110/4	0.069
321/3	0.028	110/2	0.081
322/5	0.028	110/3	0.073
323/1	0.040	118/6, 111/1	0.089
326/1	0.020	111/2	0.008
326/2	0.016	112	0.109
330/1	0.028	129/1	0.085
337/1	0.057	136/1, 134, 137, 131/3	0.121
340/2	0.008	150	0.049
341/3	0.036	151	0.024
342/1	0.012	145, 146	0.133
342/2	0.057	140	0.012
333/1	0.077	166	0.016
334	0.020	164/7	0.016
340/1	0.020	164/1	0.121
		156/2	0.032
योग	57	164/5	0.077
	2.960	163/2	0.012
		163/3	0.049
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति		161/2	0.036
से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.		149	0.016
		110/3	0.008
(3) उक्त भू-खण्ड का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी		110/6, 111/1	0.008
(राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.		113/2, 113/4	0.032
		113/1	0.077
खरसिया, दिनांक 6 दिसम्बर 2003		113/2 क	0.073
		127/2	0.016
भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य		128	0.028
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के		125/1	0.045
पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक		126	0.045
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894		120/2, 121	0.040
(क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा		120/1	0.061
यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के		119/1	0.040
लिए आवश्यकता है :—		79/2	0.053
		79/3	0.024
		75/3	0.016
(1) भूमि का वर्णन—		80/2 ख	0.061
(क) जिला-रायगढ़		81/4	0.065
(ख) तहसील-रायगढ़		81/5	0.020
(ग) नगर/ग्राम-लिटाईपाली		81/3	0.004
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.163 हेक्टेयर		81/1	0.053

अनुसूची

(1)	(2)	(1)	(2)
83/1 ख, 82	0.057	347/2	0.020
69/4 ख, 70/2 ख, 71/2 ख	0.028	351	0.190
69/1, 70/1, 71/1	0.081	287	0.045
		113/5	0.008
योग	44	346/5	0.093
	2.163	346/4	0.024
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.		345/2	0.008
		317/2	0.061
		288	0.045
(3) उक्त भू-खण्ड का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.		347/1	0.004
		346/3	0.077
		346/2	0.032
खरसिया, दिनांक 12 जनवरी 2004		357/1	0.077
		357/10	0.053
भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 148/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-		357/3	0.194
		360/1	0.109
		360/4	0.008
		317/1	0.061
		357/7	0.057
		342/5	0.032
		360/3	0.162
		315/1	0.053
		320/1	0.004
		313/1 घ	0.004
		314/2	0.028
		314/1	0.061
		320/2	0.081
		321/3	0.049
		321/4	0.004
		289	0.053
		290/9	0.020
		112/3	0.057
		290/14	0.004
		290/5	0.162
		286	0.093
		285/2	0.045
		283/3	0.061
		282/1	0.073
		290/8	0.040
		360/2	0.020
		282/2	0.061
		81/3, 82/1, 83	0.069
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)		
436	0.036		
435	0.065		
433	0.117		
432	0.045		
429/2	0.077		
429/1	0.028		
352/1	0.061		
425/3	0.069		
349/1	0.032		
349/2	0.016		

(1) (2) कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं
संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग.

84/5 0.040

रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2003

84/2 0.049

357/6 0.190

342/4 0.061

81/2, 82/2 0.065

84/1 0.073

84/4 0.045

111/3 0.065

350 0.008

योग 61 3.344

क्रमांक/क/वा. 1/अ.वि.अ./6 अ-82, 2002-2003. — चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-रायपुर

(ग) नगर/ग्राम-खामतराई, प. ह. नं. 108

(घ) लगेभाग क्षेत्रफल-0.035 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

492/1

0.035

योग 0.035

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) उक्त भू-खण्ड का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-रायपुर बिलासपुर मार्ग पर खामतराई के पास रेलवे ओवर ब्रिज, निर्माण हेतु.

(3) उक्त भू-खण्ड का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.